भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3533
17 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: खाद्य तेल पॉम ऑयल की मांग में वृद्धि
3533.श्री राम प्रसाद चौधरी:
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बढ़ते शहरीकरण और प्रसंस्कृत तथा बाह्य पदार्थों की बढ़ती खपत के कारण पॉम के खाने वाले तेल की मांग में वृद्धि हुई है; और
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा घरेलू आपूर्ति को विनियमित करने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है क्योंकि देश में खाद्य तेल की खपत में 38-40 प्रतिशत हिस्सा पॉम ऑयल का है जिसका मुख्यत: खाद्य प्रसंस्करण, होटलों, रेस्तरां और खानपान के क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है?

उत्तर
<u>कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)</u>

(क) पॉम ऑयल सहित खाद्य तेलों की घरेलू मांग उत्पादन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है।

(ख) भारत सरकार, अगस्त 2021 से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना को क्रियान्वित कर रही है, जिसका कुल स्वीकृत परिव्यय 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 11,040 करोड़ रुपये है। एनएमईओ-ओपी क्षेत्र विस्तार, उत्पादन इनपुट, बाजार समर्थन और प्रौद्योगिकी अंतरण के माध्यम से देश में ऑयल-पाम की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, तिलहनों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से वनस्पति तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओ-ओएस) शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, किसानों, प्रॉसेसर्स और उपभोक्ताओं के हितों के प्रति सामंजस्य स्थापित करने के लिए सरकार समय-समय पर ऑयल- पॉम सहित खाद्य तेलों की शुल्क संरचना की समीक्षा और जांच करती है। सरकार ने घरेलू पाम तेल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तथा घरेलू पाम तेल उत्पादकों को समर्थन देने के लिए सितंबर, 2024 में विभिन्न खाद्य तेलों पर मूल सीमा-शुल्क में वृद्धि की है।

******